

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या 3199/VII-11/09/410-उद्योग/2008
देहरादून दिनांक 10 मई 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-387/697-उ0नि0/पी0एस0/आई0ई0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांक: 388/उ0नि0-मैगा प्रोजेक्ट/08-09 दिनांक 29 अप्रैल 2008 के संदर्भ में पी0 ए0सी0सी0 लि0 द्वारा ग्राम-महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर जिला उधमसिंहनगर स्थित 70.1047 एकड़ (69.6637 एकड़ अधिसूचित तथा 0.4410 अनाधिसूचित), ग्राम-गरिचई, तहसील काशीपुर की 38.45 एकड़ अनाधिसूचित भूमि तथा ग्राम बघेलेवाला, तहसील-काशीपुर की 8.3890 एकड़ अनाधिसूचित भूमि को मैगा प्रोजेक्ट की स्थापना के अंतर्गत सीमेंट ग्राइंडिंग मैगा प्रोजेक्ट की स्थापना तथा परियोजना के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उद्योग क्षेत्र का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल
ग्राम- महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर	1/1, 1, 2, 3, 4, 6, 7मि, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30मि, 32मि, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51	70.1047 एकड़
ग्राम-गरिचई, तहसील काशीपुर	206, 207मि, 213, 209, 212मि, 212/2मि, 214मि,	38.45 एकड़
ग्राम बघेलेवाला, तहसीलकाशीपुर	272, 273, 275, 277, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285	8.3890 एकड़

2. ग्राम-महुवाखेड़ा, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-1/1, 1, 2, 3, 4, 6, 7मि, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30मि, 32मि, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 51 कुल रकबा 69.6637 एकड़ भूमि सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना-50/2003 के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून 2003 के Annexure-II के रूप में अधिसूचित है, जिस पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग (नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर) को विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमत्त होगा।

3- ग्राम महुवाखेड़ा, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या- 46 रकबा 0.4410; ग्राम गिरिचई, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-206, 207मि, 213, 209, 212मि, 212/2मि, 214मि, कुल 38.45 एकड़ तथा ग्राम बघेलेवाला, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-272, 273, 275, 277, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 कुल रकबा 8.38 एकड़ भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, इस भूमि पर केवल भारत सरकार बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7.1.2003 के अनुलग्नक-2 में दिये गये श्रष्ट उद्योगों की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमत्त होगा।

4. GIDCR-2005- में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

5. कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "सीमेंट ग्राइंडिंग" की स्थापना के लिए मैगा प्रोजेक्ट की स्थापना तथा परियोजना के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के लिए किया जायेगा।

कमरा-2-

6. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।
7. औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।
8. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, यह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।
9. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।
10. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
11. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 3199 (1)/ VII-II/09/410-उद्योग/2008 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, लांक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंहनगर।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय देहरादून/प्रबन्ध निदेशक, रिडकुल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. मै० ए०सी०सी० लि० एन०सी०आर प्लाजा, 24-ए न्यू कैण्ट रोड, देहरादून।
11. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव